हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 32 | देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 जुलाई, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

मुख्यमंत्री ने धोए कांवड़ियों के पांव, अद्भुत दिखा नज़ारा 3

प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना, इन जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट

संजय कुमार की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

धीरे-धीरे बारिश का मौसम अपना असली रूप दिखाने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, देहरादून सहित उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने 20 जुलाई के रेड अलर्ट के अपने पूर्वानुमान को जारी रखा है। इसके साथ ही 21 व 22 के लिए भी राज्य के पर्वतीय जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। पहले भी मौसम विभाग ने मंगलवार की भारी से बहुत भारी बारिश का नोटिस जारी किया था और इन जिलों को रेड अलर्ट में रखा था। आज फिर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत, उधमसिंहनगर, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

इस लिए आज इन आठ ज़िलों के स्कूल को बंद करवा दिया है। इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। वहीं 21 के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत, उधमसिंहनगर व हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश होने के साथ कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट यथावत रखा गया है। शेष जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 21 को देहरादून सहित रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व नैनीताल में कहीं-कहीं भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट है। 22 को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले के लिए कहीं कहीं भारी बारिश का यलो अलर्ट है। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार अलर्ट के चलते प्रदेश में संवेदनशील इलाकों में मध्यम से बड़े भूस्खलन व चट्टान खिसकने के कारण सड़कों में अवरोध, कटाव की समस्या हो सकती है। नदी नालों में अतिप्रवाह, निचले इलाकों में जल भराव की समस्या हो हो सकती है।

7 अगस्त को भू–कानून / मूल निवास मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास मार्च करेंगे राज्य आंदोलनकारी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

शहीद स्मारक में भू–कानून एवं मूल निवास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई जिसमे काफी संख्या में मातृ शक्ति ने भाग लिया। बैठक में सभी राज्य आंदोलनकारियों ने क्रांति दिवस से एक दिन पूर्व 7–अगस्त को गांधी पार्क से मुख्यमंत्री कार्यालय मार्च हेतु सहमति जताते हुए हाथ उठाकर संकल्प लिया है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी वेद प्रकाश शर्मा एवम जगमोहन सिंह नेगी ने सरकार से पुरजोर अपील करते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द हिमाचल की तर्ज पर भू–कानून लागू करे एवम 2018 का भू कानून तत्काल निरस्त करे। उन्होंने कहा कि हमने जिस उद्देश्य को लेकर राज्य का गठन हुआ था वह अब लूटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि न हम अपनी भूमि ही बचा पा रहे है और ना ही मूल निवास का अधिकार उत्तराखंडी को मिल पा रहा है। बैठक का संचालन महामंत्री डी एस गुसाई द्वारा किया गया जबकि अध्यक्षता सांस्कृतिक मोर्चे की अध्यक्ष सुलोचना भट्ट जी द्वारा की गई। ऋषिकेश से विक्रम भण्डारी एवम रामलाल जी ने कहा कि हम अपेक्षा करते है कि भू कानून हेतु बनी कमेटी जल्द से जल्द स्कारात्मक दृष्टिकोण से सभी के सुझावों को अमल में लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे , साथ ही उन्होंने बताया कि 24–जुलाई को

गांधी पार्क में भू कानून संयुक्त मोर्चा के तहत धरना दिया जायेगा। मसूरी से देवी गोदियाल व बलबीर सिंह नेगी ने सभी राज्य आंदोलनकारियों व संस्थाओं से अपील की है कि क्रांति दिवस के एक दिन पूर्व दिनांक 7 अगस्त को प्रातः 11 बजे अधिक से अधिक व्यक्ति भू–कानून/मूल निवास लागू करने हेतु के लिए अपनी आवाज बुलन्द करने मुख्यमंत्री कार्यालय मार्च में शामिल हों। बैठक में मुख्यत पुष्पलता सिलमाना, जगमोहन सिँह नेगी , सुलोचना भट्ट , विक्रम भंडारी , सुरेश नेगी , डी० एस० गुसांईं , रेनू नेगी , सरोजनी थपलियाल , वेद प्रकाश शर्मा. बलबीर सिँह नेगी , देवी गोदियाल , गंभीर मेवाड़. पूरण जुयाल , गुलाब सिँह , अरुणा थपलियाल , सरोज रावत , कमला खंतवाल, देवश्वरी गुसांईं , सुभागा भरसवान , संतन रावत , राजेश्वरी डोबरियाल , निर्मला बिष्ट , बीना बहुगुणा , मंजू भट्ट , शिव प्रसाद जोशी , प्रभात डंडरियाल , अमित तिवाड़ी , आशा उनियाल , यशोदा रावत , गोदाम्बरी देवी , प्रेम सिंह नेगी , धर्मा नन्द भट्ट, कल्पेश्वरी नेगी , पार्वती नेगी , पूनम मैखुरी. यशोदा ममगाई , युद्ध वीर सिँह चौहान , संगीता उनियाल , विमला बहुगुणा , सुरेश कुमार एवम नवनीत गुसाईं , विनोद

कावड़ व्यवस्था को लेकर डीएम और एमएसपी अलर्ट मोड पर

महवीश
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ऋषिकेश, 20 जुलाई । जिलाधिकारी,देहरादून श्रीमती सोनिका एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुँवर ने आज संयुक्त रूप से नगर निगम सभागार ऋषिकेश में कावड़ यात्रा हेतु की गई विभिन्न व्यवस्थाओं एवं तैयारियों की समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रा हेतु प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस विभाग द्वारा नियुक्त जोनल एवं सेक्टर प्रभारियों संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार ऋषिकेश को निर्देश दिए कि रेलवे स्टेशन के समीप सड़क की मरम्मत करने हेतु रेलवे को पत्राचार किया जाए। साथ ही नगर निगम को सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला पंचायत विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा रूट पर प्रकाश की व्यवस्था करने के निर्देश दिए । उन्होंनें संबंधित अधिकारियों को यात्रा रूट पर चाकचैबंद साफ-सफाई व्यवस्था, पेयजल, बायो टॉयलेट, जानवरों से सुरक्षा, कीटनाशकों का छिड़काव, प्रकाश व्यवस्था, विभिन्न स्थानों पर एंबुलेंस की तैनाती, वाहनों पर किराया सूची, होटल, रेस्टोरेंट एवं खाद्य सामग्री की दुकानो पर रेट लिस्ट चस्पा करवाने के निर्देश दिए। उन्होनें पुलिस तथा जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए सैक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट को आपस में एक-दूसरे का नंबर साझा करने एवं समन्वय बनाते हुए यात्रा का संचालन करने के निर्देश भि दिए ।

उन्होंने प्रशासन द्वारा कावंड़ यात्रा हेतु नियुक्त जोनल एवं सैक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस विभाग के जोनल एवं सैक्टर प्रभारियों को आपस में समन्वय करते हुए दायित्वों का संपादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल प्रभारी एवं सैक्टर मजिस्ट्रेट एवं सैक्टर प्रभारियों को अपने-अपने ड्यूटी पॉइंट पर निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं देखने को कहा तथा यदि कहीं पर और सुधार की आवश्यकता हो तो उसे यथाशीघ्र पूर्ण करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने पुलिस को सुरक्षा के दृष्टिगत सर्तक रहते हुए कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कमलेश उपाध्याय, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश बद्री प्रसाद भट्ट, तहसीलदार ऋषिकेश अमृता शर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी डीसी ढोडियाल, नियुक्त किए गए जोनल एवं सैक्टर मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी सहित सिंचाई, राष्ट्रीय राजमार्ग, पेयजल निगम, स्वास्थ्य, जल संस्थान, लो.नि.वि, विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

जानें कैसे बागवानी मानसिक स्वास्थ्य में मदद कर सकता है

संजय कुमार की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

घर में गार्डन बनाने का सपना तो सभी का होता है, लेकिन कभी जगह की कमी तो कभी जानकारी की कमी से यह सपना पूरा नहीं हो पाता। घर में पौधे होने से घर के साथ आसपास का वातावरण भी स्वच्छ हो जाता है। इसके फायदे बहुत हैं लेकिन एक फायदा ऐसा भी है जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं। टीम न्यूज़ वायरस आपको इस खबर में उन फायदों के बारे में बताएगा।मानसिक स्वास्थ्य अभी भी एक बहुत अच्छा विषय है और हर कोई इस स्थिति पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। हालांकि, इस पर चर्चा करने या न करने से यह तथ्य नहीं बदलता है कि ऐसे लोग हैं जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति से पीड़ित हैं जो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित लोगों को आमतौर पर निर्धारित दवाएं और उपचार दिए जाते हैं। हालांकि, हल्की स्थितियों से पीड़ित लोग चिकित्सा और अन्य तरीकों का सहारा ले सकते हैं जो उनकी चिंता को कम करते हैं और उन्हें शांत महसूस कराते हैं। लोग खुद को शांत करने के लिए पेंटिंग कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं या बागवानी का अभ्यास कर सकते हैं।बागवानी मानसिक स्वास्थ्य में मदद कर सकती है और यह आराम करने, ध्यान केंद्रित करने और तनाव मुक्त करने में भी मदद करती है। साथ ही, बागवानी सामान्य रूप से पौधों, प्रकृति और पर्यावरण के बारे में अपने ज्ञान को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। हालांकि बागवानी का अभ्यास कोई भी कर सकता है और इसे एक शौक के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।

दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर उठ रहे सवालों पर निर्मला सीतारमण ने तोड़ी चुप्पी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि गेहूं के आटे और अन्य वस्तुओं पर पांच प्रतिशत कर लगाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि गैर-भाजपा शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल ने 5 फीसदी शुल्क लगाने पर सहमति जताई है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, सीतारमण ने कहा कि राज्यों ने पूर्व-वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) शासन में खाद्यान्न पर बिक्री कर या वैट लगाया और रिसाव को रोकने के लिए अनाज, दाल, आटा, दही और लस्सी पर वर्तमान लेवी लगाई। अभ्यास है।

उन्होंने कहा कि निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया गया था, जहां सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व आम सहमति से किया गया था। मंत्री की टिप्पणी संसद के मानसून सत्र के पहले दो दिनों की पृष्ठभूमि के खिलाफ आई है, जो दैनिक उपयोग की वस्तुओं और अन्य मुद्दों पर जीएसटी पर विपक्षी दलों के मुखर विरोध के कारण लगभग धुल गई है।"क्या यह पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है? नहीं, राज्य जीएसटी पूर्व व्यवस्था में खाद्यान्न से महत्वपूर्ण राजस्व एकत्र कर रहे थे। अकेले पंजाब ने खरीद कर के माध्यम से खाद्यान्न पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह किया। यूपी ने 700 करोड़ रुपये एकत्र किए। सीतारमण ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए पंजाब तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और बिहार में 2017 से पहले लगाए गए चावल पर वैट का भी हवाला दिया। हालांकि, ट्वीट में दाल, पनीर और लस्सी पर कर लगाने के उदाहरण नहीं दिए गए, जैसा कि अब होता है। हाल ही में, जीएसटी परिषद ने अपनी 47 वीं बैठक में दाल, अनाज, आटा, आदि जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की थी। इस बारे में बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई है,₹ मंत्री ने कहा।जब जुलाई 2017 में जीएसटी शासन, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य वैट सहित 17 केंद्रीय और राज्य कर शामिल थे, को पेश किया गया था, 'ब्रांडेड' अनाज, दाल और आटे पर 5 प्रतिशत कर लगाया गया था।₹बाद में केवल उन सामानों पर कर लगाने के लिए संशोधन किया गया, जो पंजीकृत ब्रांड या ब्रांडों के तहत बेचे गए थे, जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा लागू करने योग्य अधिकार नहीं छोड़ा गया था. ₹हालांकि, जल्द ही इस प्रावधान का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग प्रतिष्ठित निर्माताओं और ब्रांड मालिकों द्वारा देखा गया और धीरे-धीरे इन वस्तुओं से जीएसटी राजस्व में काफी गिरावट आई।₹उन्होंने कहा कि आपूर्तिकर्ताओं और उद्योग संघों ने सरकार से इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी पैकेज्ड सामानों पर समान रूप से जीएसटी लगाने को कहा है। इस मुद्दे को राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात के अधिकारियों की एक फिटमेंट समिति के पास भेजा गया था। उन्होंने कहा कि पैनल ने कई बैठकों में इस मुद्दे की जांच की और दुरुपयोग को रोकने के तौर-तरीकों में बदलाव के लिए अपनी सिफारिशें कीं।समिति की सिफारिशों की जांच पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार के सदस्यों से बने मंत्रियों के एक समूह ने की और इसकी अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने की। पिछले महीने चंडीगढ़ में हुई बैठक में जीओएम की सिफारिश को नई कर व्यवस्था के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय जीएसटी परिषद के समक्ष रखा गया था। यह इस संदर्भ में है कि जीएसटी परिषद ने अपनी 47 वीं बैठक में निर्णय लिया। 18 जुलाई, 2022 से इन वस्तुओं पर केवल जीएसटी लगाने के तौर-तरीकों में बदलाव किया गया, जिससे जीएसटी के दायरे में 2-3 वस्तुओं को छोड़कर कोई नहीं बचा।₹प्री-पैकेज्ड और लेबलर₹ की आपूर्ति की जाने वाली इन खाद्य वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया था। उदाहरण के लिए, दालें, अनाज जैसे चावल, गेहूं और आटा, आदि पर पहले 5% जीएसटी लगता था जब ब्रांडेड और यूनिट कंटेनरों में पैक किया जाता था। 18.7.2022 से 'प्री-पैकेज' होने पर इन वस्तुओं पर जीएसटी लगेगा। और लेबल किया जाएगा। हालांकि, खुले में बेचे जाने पर दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, मुरमुरे और दही/लस्सी पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और पहले से पैक या प्री-लेबल नहीं होगा।यह जीएसटी परिषद द्वारा एक सर्वसम्मत निर्णय था। 28 जून, 2022 को चंडीगढ़ में आयोजित 47वीं बैठक में दरों के युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह द्वारा मुद्दा प्रस्तुत किए जाने पर सभी राज्य जीएसटी परिषद में मौजूद थे। सीतारमण ने कहा, ₹गैर-भाजपा राज्यों (पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल) सहित सभी राज्य इस फैसले से सहमत हैं। जीएसटी परिषद का यह फैसला एक बार फिर आम सहमति से है। उन्होंने कहा कि जीओएम द्वारा बदलावों की सिफारिश की गई थी और ₹कर रिसाव को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था।निष्कर्ष के लिए: यह निर्णय कर रिसाव को रोकने के लिए एक बहुत ही आवश्यक था। अधिकारियों, मंत्रियों के समूह सहित विभिन्न स्तरों पर इस पर विचार किया गया था, और अंत में जीएसटी परिषद द्वारा सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति के साथ सिफारिश की गई थी,₹ उसने कहा। बताया।₹

हिंदी दैनिक
न्यूज़ वायरस

मुख्यमंत्री ने धोए कांवड़ियों के पांव, अद्भुत दिखा नज़ारा

फ़िरोज़ आलम गांधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में डामकोठी के निकट गंगा घाट पर शिव भक्तों का स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ यात्रा में देवभूमि उत्तराखण्ड आये शिव भक्तों के चरण धोकर एवं गंगाजली देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मां गंगा की कृपा सभी पर बनी रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डामकोठी में वृक्षारोपण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड आये शिव भक्तों में भगवान शिव का अंश दिखता है। उन्होंने कहा कि कांवड़ की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, इसके लिए सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के लिए पहली बार अलग से बजट की व्यवस्था की गई। सभी कांवड़ श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। श्रद्धालुओं को राज्य में कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। कांवड़ मेले के सुचारू प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री ने सामाजिक संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, शासन एवं जिला प्रशासन के कार्यों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में इस वर्ष चारधाम एवं कांवड़ में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी तक 27 लाख से अधिक रजिस्टर्ड श्रद्धालु चारधाम दर्शन के लिए आ चुके हैं। आज 28 लाख से अधिक कांवड़ यात्री देवभूमि उत्तराखण्ड में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना न करने पड़े, इसके लिए उच्च स्तर पर एक वाट्सप ग्रुप भी बनाया गया है, इस ग्रुप के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है, मुख्यमंत्री स्वयं इस ग्रुप से जुड़े हैं। इस अवसर पर विधायक आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, डीआईजी गढ़वाल के. एस. नगन्याल, जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पाण्डेय, एस.एस.पी डॉ. योगेन्द्र सिंह रावत, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन एवं शिवभक्त मौजूद थे।

भारी बरसात के अलर्ट पर सतर्क है सरकार सीएम धामी ने सम्हाली कमान

फ़िरोज़ आलम गांधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

राज्य में भारी बरसात के अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम जाकर राज्य की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश की सम्भावना को देखते हुए लगातार अलर्ट रहने की जरूरत है। आपदा को लेकर की गयी तैयारियों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाए। कोई भी कमी पाए जाने पर तुरंत सुधार किया जाए। किसी भी अधिकारी का मोबाईल स्विच ऑफ न हो। इसमे कोई बहाना नहीं चलेगा। अपनी ड्यूटी में लापरवाही करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी अपने जिलों की स्थिति के अनुसार स्कूलों में छुट्टी के संबंध में निर्णय लें। किसी तरह की असावधानी न बरती जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि खाद्यान्न, दवाइयां, ईंधन आदि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। संचार नेटवर्क में कोई समस्या न आए इसके लिये मोबाईल आपरेटर कम्पनियों से लगातार समन्वय रखा जाए। मुख्यमंत्री ने ऐसा सिस्टम बनाने को कहा कि राज्य मुख्यालय से प्रसारित सूचना गांव गांव तक अविलंब पहुंच जाए। सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष आपदा की दृष्टि से अपने-अपने विभागों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करे। आपदा की स्थिति में प्रभावितो के रहने के लिये चिन्हित भवनों और स्थानों का फिर से सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षण किया जाए। नये व युवा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। इस दौरान सीएम को अधिकारीयों ने जानकारी दी कि पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। रियल टाईम मानिटरिंग की जा रही हैं। भूस्खलन से रास्ते बंद होने पर तुरंत खोलने के लिए विभिन्न स्थानों पर जेसीबी आदि लगाई गयी हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों की दीर्घकालिक अवकाश पर रोक है। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु, सचिव डॉ रंजीत सिन्हा व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अपने राशन कार्ड को रद्द होने से बचाए , जाने ये ताजा नियम

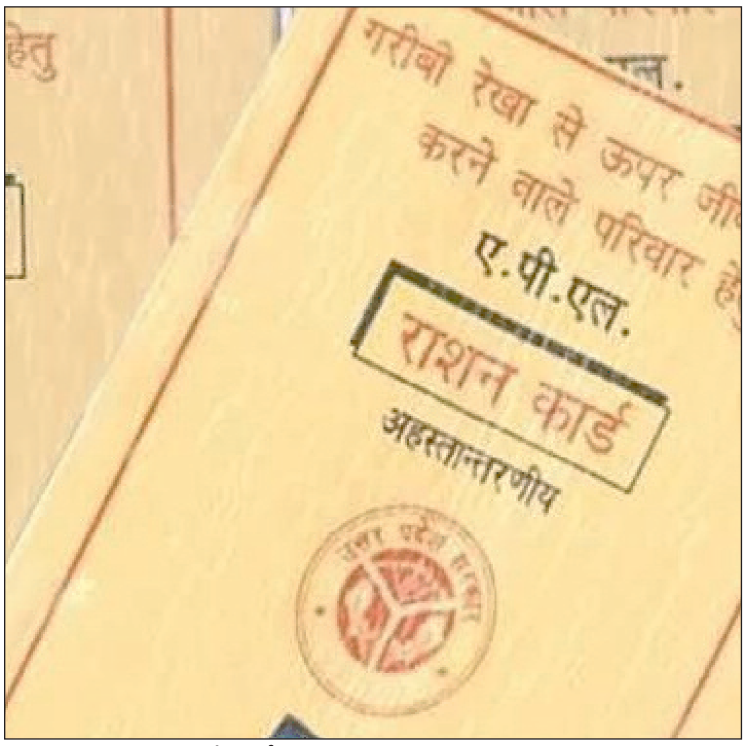

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

राशन कार्ड के बदले नियम, यह खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए।अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो। हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों के लिए फ्री राशन की व्यवस्था शुरू की गई जिसका अपात्र लोग भी सरकार की 'मुफ्त राशन योजना' का फायदा उठा रहे हैं. परंतु सरकार ने इन खबरों का किया खंडनपिछले दिनों कई मीडिया में प्रकाशित खबरों में दावा किया गया था कि सरकार की तरफ से अपात्र लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की जा रही है. खबरों में यह भी दावा किया गया कि जो लोग राशन कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस खबर का पता चलने के बाद यूपी सरकार ने इस पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है.अब आप को राशन कार्ड से जुड़े नियमो के बारे में पूरी जानकारी बता देते हे वरना हो सकती है कार्रवाई हालांकि जिरूरी नही है कि आपको राशन कार्ड से जुड़े नियमो के बारे में पूरी जानकारी हो।यदि आपने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है और उस पर सरकार की राशन योजना फायदा ले रहे हैं तो आपकी कोई भी शिकायत कर सकता है. इतना ही नहीं जांच में शिकायत के सही पाए जाने पर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है.आइए जानते हैं क्या हैं नियम ?यदि किसी कार्ड धारक के पास खुद की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लाट/ फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी / ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक पारिवारिक आय है तो ऐसे लोग सरकार की सस्ते राशन योजना का

उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने घांस के गट्ठर के साथ घेर लिया कलेक्ट्रेट ज़ोरदरा हुआ प्रदर्शन

हेलंग घाटी में महिलाओं की अस्मिता का हुआ अपमान - ज्योति रौतेला

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड के चमोली जिले के हेलंग घाटी में ग्रामीण महिलाओं से घास छीनने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मौजूद अधिकारियों की निंदा की जा रही है. वहीं, पहले वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मामले की जांच जिलाधिकारी से कराए जाने की बात कहते हुए महिलाओं को ही गलत ठहरा दिया है , वहीँ अब विपक्षी कांग्रेस की महिला ब्रिगेड ने मोर्चा खोल दिया है।

उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने आज एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करते हुए मजबूत विपक्ष का नज़ारा पेश किया है। स्टेट प्रेसिडेंट ज्योति रौतेला के नेतृत्व में जनता से जुड़े मुद्दों पर सड़कों पर आंदोलन करते हुए बीते कुछ ही महीनों में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज़ कराई है। एक बार फिर आज महिला कांग्रेस की टीम ने एक बार फिर हेलंग (चमोली) में पुलिस प्रशासन द्वारा घास ले जा रही महिला की घास छीन कर गिरफ्तार करने की घटना पर मोर्चा खोला और जोरदार नारेबाजी और अनोखे अंदाज़ में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को मेमोरेंडम भेजा है। इसके पहले प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि पहाड़ की महिलाओं से इस तरह का दुर्व्यवहार भाजपा सरकार में बेहद शर्मनाक और उत्तराखंडी अस्मिता व स्वाभिमान के लिए बड़ी चुनौती है।

चमोली जिले का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें कई सवाल खड़े कर दिए हैं. हेलंग घाटी में घास ले जाती 2 महिलाओं से सीआईएसएफ और पुलिस जवानों की नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हुआ है. मामले के तहत इसके बाद पुलिस कर्मियों ने इन महिलाओं को कई घंटे तक थाने में बैठा कर रखा और फिर 250 रुपए का चालान भी किया. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों समेत आम लोगों ने भी घटना की निंदा करनी शुरू कर दी. जिसके बाद ये मामला मीडिया और फिर सरकार के सामने भी पहुंचा है। लेकिन कांग्रेस ने इसको पहाड़ की महिलाओं

कांग्रेस पार्षद कोमल बोरा के साथ हुए अभद्र व्यवहार की शिकायत लेकर डीजीपी से मिले कांग्रेसी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड कांग्रेस के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर देहरादून महानगर में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे नशे के अवैध करोबार पर रोक लगाये जाने तथा वार्ड नं0 32 की कांग्रेस पार्षद कोमल बोरा के साथ हुए अभद्र व्यवहार की शिकायत पर कानूनी कार्रवाये जाने की मांग की।पुलिस महानिदेशक को सौंपे पत्र में कांग्रेस ने कहा कि राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुडे असामाजिक तत्वों की ओर आकर्षित कराना चाहते है । जहां एक ओर देहरादून महानगर के विभिन्न क्षेत्रों जिनमें पटेलनगर, मेहूवाला, राजीव नगर, डालनवाला, बिन्दाल बस्ती, मित्रलोक कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, निम्बूवाला डीडी कॉलेज के पास, चोरखाला व डाकरा हवा घर के पास, पूरण बस्ती भाग दो, आर्य नगर आदि क्षेत्रों में विगत काफी लम्बे समय से नशीले पदार्थों के कारोबार को खुलेआम चलाया जा रहा है वहीं पंजाब में नशे के खिलाफ वरती जा रही सख्ती के उपरान्त नशे के कारोबारियों द्वारा उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून में अपने कारोबार बढाने की घटनायें गम्भीर चिन्ता का विषय हैं।

पुलिस महानिदेशक को सौंपे एक अन्य पत्र में महानगर कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि नगर निगम द्वारा चलाये गये अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान महानगर के वार्ड नम्बर 32, बल्लूपुर के कौलागढ़ रोड पर होटल चटनी मैरी के सामने कॉम्प्लेक्स स्वामी द्वारा नगर निगम के नाले को पाट कर कराये गये सी.सी. निर्माण करा दिया गया था। इसका विरोध करते हुए स्थानीय पार्षद कोमल वोहरा ने शिकायती पत्र के माध्यम से. मेयर नगर निमगम देहरादून, आयुक्त नगर निगम देहरादून, स्वास्थ्य अधिकारी देहरादून को अवगत करा दिया गया कि कॉम्प्लेक्स स्वामी द्वारा सरकारी बरसाती नाले को पाट कर अपनी निजी पार्किंग बनवाया गया है। कॉम्प्लेक्स स्वामी द्वारा नगर निगम अधिकारीगणों को सरेआम धमकियाँ दी गई तथा महिला पार्षद को भी सरे आम गाली गलौच करके जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया कि मामले का संज्ञान लेते हुए मामले में उचित कार्रवाई हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रतिनिधिमण्डल में महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा के अलावा पूर्व विधायक राजकुमार, आनन्द त्यागी, अनुराग गुप्ता, मीना रावत, कोमल बोहरा, संगीता गुप्ता, अमृता कौशल, प्रवेश त्यागी, सुनील बांगा एवं रीता रानी शामिल थे।

मंत्री रेखा आर्य करेंगी 25 KM की कांवड़ यात्रा, बेटी बचाओ का देंगी सन्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड में लिंगानुपात को सुधारने के लिए विभागीय मंत्री रेखा आर्य अब भगवान शिव की शरण में जाने वाली हैं। आपको सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन योजना यही है कि कांवड़ यात्रा में पदयात्रा कर बेटी बचाओ का सन्देश दिया जाये। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बड़ा संकल्प लिया है। प्रदेश में लिंगानुपात को समान करने के लिए उन्होंने शिवरात्रि के दिन से एक अभियान शुरू करने की बात कही हैं। मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि 26 जुलाई को हरकी पैड़ी से मां गंगा के पूजन और साधु संतों के आशीर्वाद साथ यह अभियान शुरू किया जाएगा. 'देवियों की भूमि' स्लोगन के साथ अभियान का शुभारंभ किया जाएगा. उसके बाद वहां से जल भरकर मंत्री रेखा आर्य कांवड़ियों के साथ करीब 25 किमी पैदल यात्रा करेंगी

जिसके बाद करीब 1300 वर्ष पुराने अंतिम पड़ाव वीरभद्र मंदिर में मुख्यमंत्री के साथ भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ संकल्प लिया जाएगा. मंत्री रेखा आर्य को विश्वास है कि इससे प्रदेश की रजत जयंती पर उत्तराखंड में लिंगानुपात समान होगा और देवियों की भूमि से एक संकीर्ण मानसिकता का विनाश होगा.महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा. वह पैदल कांवड़ यात्रा कर इस अभियान को शुरू करेंगी, तो प्रदेश के सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास से जुड़े अधिकारी कर्मचारी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के अभियान के लिए अपने नजदीकी शिवालयों में इस दिन जलाभिषेक करेंगी....

मंत्री रेखा आर्य ने की जनमानस से भावुक अपील --

उन्होंने कहा कि बेटियों को गृभ में ही मार देना या फिर भ्रूण का परीक्षण कराना एक दंडनीय अपराध है लेकिन फिर भी अमूमन यह देखने मे आया है कि इस तरह के कृत्य अभी भी चोरी छिपे कुछ पैथोलॉजी/नर्सिंग होम/अस्पताल करते हैं। मंत्री ने ये स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करने वालों की सूचना विभाग को टोल फ्री नंबर 181 पर देंगे उनकी गोपनीयता को छुपाया जाएगा और ऐसे काम करने वालो पर सख्त कार्यवाही की जाएगी,साथ ही सूचना देने वालो को पारितोषिक दिया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सभी से अपील करते हुए कहा कि मैं सभी माताओ,बहनों से यह अपील करती हू कि इस कार्यक्रम को सिर्फ एक दिन का ना समझे । यह आपके त्याय,बलिदान,सर्मपण और आपके हकों के लिए हैं । हमें इसके जरिए लैगिंक असमानता और रूढिवादिता की बेढियों को तोडना है। मैं सभी बहनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक भागीदारी करने का आहवाहन करती हू।

विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल ने उठाये महत्वपूर्ण कदम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(से नि) ने राजकीय विश्वविद्यालयों में कुलपति चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग करने के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। हाल ही में उत्तराखण्ड तकनीकि विश्वविद्यालय और उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हेतु कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया में इसकी शुरूआत भी हो गई है। राजकीय विश्वविद्यालयों की कुलपति चयन प्रक्रिया में सरकार द्वारा गठित सर्च कमेटी द्वारा 3 से 5 नाम राजभवन प्रेषित किये जाते हैं। नई प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पैनल में सम्मिलित कुलपति पद के प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उत्तराखण्ड तकनीकि विश्वविद्यालय के कुलपति चयन के साथ इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है जब पैनल में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों का औपचारिक साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार में राज्यपाल के साथ-साथ उनके द्वारा निर्दिष्ट राजभवन के उच्च अधिकारियों का पैनल भी रहता है। कुलपति पद के अभ्यर्थी से अकादमिक, प्रशासनिक, मनौवैज्ञानिक, उनकी अभिरूचि, उनके विजन, उनकी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की जाती है। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद हेतु चयन साक्षात्कार में इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रारम्भ कर दी गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(से नि) का निर्देश है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और जवाबदेही तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब कुलपति पद सहित विश्वविद्यालय की सभी नियुक्तियाँ पूर्ण पारदर्शिता एवं स्वच्छता के साथ हो। यही नहीं, राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर आदि शैक्षणिक पदों पर होने वाले साक्षात्कार की वीडियो रिकार्डिंग करने हेतु व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये हैं। विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद की बैठकों में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु रिकार्डिंग शुरू की जायेगी। इस हेतु आवश्यकता पड़ने पर परिनियमों में संशोधन भी किया जायेगा। राजभवन में साक्षात्कार की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी बनाते हुए इसकी रिकार्डिंग करते हुए इसकी शुरूआत कर दी गई है।सशक्तिक

उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति हो रही भयावह, आज मिले 189 नए मामले; दो संक्रमितों की हुई मौत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

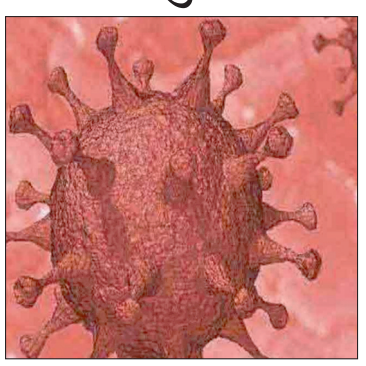

देहरादूनः उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। पिछले दो सप्ताह से राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को कोरोना के 189 नए मरीज मिले हैं। जबकि कोरोना संक्रमित दो मरीजों की मौत भी हुई है।

कोरोना संक्रमण दर 10 प्रतिशत को पार कर गई है। यह 10.65 प्रतिशत दर्ज की गई है। राहत बस इस रूप में है कि विभिन्न जनपदों में 100 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं।

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, निजी व सरकारी लैब से 1775 सैंपल की जांच रिपोर्ट मिली है। जिनमें 1586 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। देहरादून जनपद में लगातार दूसरे दिन संक्रमितों की संख्या सैकड़ा पार गई गई है।

यहां 113 लोग संक्रमित मिले हैं। यह कुल मामलों का 60 प्रतिशत है। वहीं, संक्रमण दर भी 16 प्रतिशत रही है। इसके अलावा नैनीताल में 40, हरिद्वार में 16, अल्मोड़ा में आठ. ऊधमसिंहनगर में पांच, पौड़ी गढ़वाल व उत्तरकाशी में तीन-तीन और चमोली में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पाजिटिव आई है। बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग व टिहरी गढ़वाल में कोरोना का कोई नया मामला नहीं मिला है।

इधर, विभिन्न जनपदों से 1835 सैंपल कोरोना जांच को भेजे गए हैं। बता दें, इस साल प्रदेश में कोरोना के 95164 मामले आए हैं। जिनमें 90752 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इस साल कोरोना संक्रमित 286 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 750 पहुंच गई है। जिनमें सबसे ज्यादा 540 सक्रिय मामले देहरादून जनपद में हैं। वहीं, नैनीताल में 75 व हरिद्वार में 66 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में 12, ऊधमसिंहनगर व उत्तरकाशी में 11-11, पौड़ी गढ़वाल में दस, चमोली व टिहरी गढ़वाल में आठ, पिथौरागढ़ में छह, बागेश्वर में दो व रुद्रप्रयाग में एक सक्रिय मामला है। वहीं, चंपावत में अभी कोई सक्रिय मामला नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जांच का आंकड़ा सीमित है। पिछले 20 दिन में राज्य में साढ़े 27 हजार के करीब सैंपल की जांच की गई है। इस हिसाब से हर दिन 1300 के करीब ही जांच अभी की जा रही है। उसमें भी पहाड़ी जिलों में बेहद कम जांच की जा रही है। बुधवार को भी अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ व रुद्रप्रयाग से जांच को भेजे गए सैंपल की संख्या दहाई में रही है। एक बस देहरादून जनपद है, जहां जांच का आंकड़ा 500 के पार है।

पर्वतीय ठेकेदार संघ समिति ने पीडब्ल्यूडी रॉयल्टी बढ़ोत्तरी मांमले में की स्पीकर से मांग

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

लोक निर्माण विभाग के कार्यों में रायल्टी की दरों में पांच गुनी बढ़ोतरी को निरस्त किए जाने एवं रॉयल्टी की कटौती पूर्व की भांति रखे जाने के सम्बन्ध में पर्वतीय ठेकेदार संघ समिति, पौड़ी गढ़वाल के शिष्टमंडल ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण से देहरादून स्थित उनके शासकीय आवास पर भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने ठेकेदार संघ को आश्वस्त करते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कही।

ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को अवगत किया कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों में रायल्टी की दरों में पांच गुनी बढ़ोतरी से छोटे और मध्यम स्तर के ठेकेदार विभाग की निविदा ही नहीं ले पाएंगे। इससे उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। ठेकेदारों ने रायल्टी बढ़ाए जाने का फैसला वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा की सरकार द्वारा जारी खनन संबन्धी जारी नियमों को पूर्ण करना ठेकेदार के लिए असंभव हैं। ठेकेदारी व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के समक्ष आजीविका का संकट व्याप्त हैं तथा प्रदेश भर के सभी ठेकेदार व ठेकेदार संघ आकोशित हैं। ठेकेदारों ने इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष से शासनादेश को मुख्यमंत्री के द्वारा अविलम्ब निरस्त करने का आग्रह किया।

विधानसभा अध्यक्ष ने ठेकेदारों की बात सुनने के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु एवं खनन सचिव पंकज पांडे से वार्ता की एवं संबंधित विषय के शासनादेश के बारे में जानकारी ली ।उन्होंने ठेकेदार संघ को आश्वस्त करते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी वार्ता करने की बात कही ।

बरसात के मौसम में परेशान कर रहे हैं मच्छर और मक्खियां, अपनाएं ये टिप्सरेंज

संजय कुमार की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

बरसात का मौसम आ गया है। बारिश अपने साथ मच्छर और मक्खियां भी लेकर आती है। बारिश के कारन उमस भी बहुत हो जाती है इसलिए घर के खिड़की दरवाजे भी खोलने पड़ते है, और अगर आप घर के खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं तो मच्छर और मक्खियां बड़े मौज से आपकी मेहमान बनकर आ जाती हैं. खासकर जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहां दिन में दस बार दरवाजे खुलते और बंद होते हैं. ऐसे में मक्खियां दुनियाभर की गंदगी आपको बीमार करने के लिए अपने साथ लेकर आती हैं. अगर बीमारी का खतरा ना भी देखें तो इनकी भिन-भिन चैन से सोने-बैठने नहीं देती. पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जो आपके घर से इन मक्खियों को भागने पर मजबूर कर देंगे.

एपल साइडर विनेगर एक गिलास में एपल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका लें और उसमें डिश सोप की कुछ बूंदें मिला लें. अब किचन में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक रैप को लेकर इस गिलास को ढक दें और गिलास पर प्लास्टिक रैप को रबड़ लगाकर टाइट कर लें. इसके बाद एक टूथपिक लेकर गिलास के मुंह पर लगे प्लास्टिक रैप पर जगह-जगह छेद कर दें. मक्खियों वाली जगह पर इसे रखें. जैसे ही मक्खियां इस गिलास पर आएंगी या अंदर जाने की कोशिश करेंगी तो डिश सोप के कारण बाहर नहीं निकल पाएंगी और अंदर ही डूबने नमक का पा एक गिलास पानी में 2 चम्मच भरकर नमक लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए. अब इस पानी को एक स्प्रे बोतल में भरिए और मक्खियों पर छिड़किए. यह मक्खियों को भगाने के लिए बेहद अच्छा है. पुदीना और तुलसी मक्खियों को भगाने के लिए पुदीना और तुलसी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. आप इन दोनों का पाउडर या पेस्ट बनाकर पानी में मिला सकते हैं. इस पानी को मक्खियों पर स्प्रे करें. यह कीटनाशक की तरह असर दिखाता है. दूध और काली मिर्च से नुस्खे को तैयार करने के लिए एक गिलास दूध में एक चम्मच काली मिर्च और 3 चम्मच चीनी मिला लें. जहां भी मक्खियां सबसे ज्यादा घूमती हैं वहां इस दूध को रखें. मक्खियां इसकी तरफ आकर्षित होंगी लेकिन जल्द ही इससे चिपक कर डूब जाएंगी. फ्लाईट्रैप यह एक कार्निवोरस पौधा है जो कीड़े-मकौड़े खाता है. वीनस फ्लाईट्रैप पौधे को घर के बाहर या अंदर 1-2 कोनों पर लगा लें. इन पौधों का मुंह खुला रहता है और जैसे ही मक्खी इन पर आकर बैठती है तो ये उसे दबोच लेते हैं.

भारत में है इलेक्ट्रिक स्कूटरों की भारी मांग, ये है देश का सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें कीमत और रेंज

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की भी भारत में भारी डिमांड हो रही हे। लोग अब इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रति ज़्यादा रुचि दिखा रहे हे। ऐसे में टीम न्यूज़ वाइरस इस ख़बर के माध्यम से आपको देश की सबसे दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बतायेंगे जिसको सिंगल में चार्ज मिलेगी 200KM और किमत महज 50,000 रुपय.निर्माता एथर एनर्जी जल्द ही अपने लोकप्रिय बैटरी पावर्ड स्कूटर 450X का अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने की योजना बना रही है ।एथर एनर्जी फिलहाल अपडेटेड 2022 एथर 450X प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रही है और इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। अपडेटेड एथर 450X का फेसलिफ्टेड वर्जन होने की उम्मीद है और इसमें कुछ विजुअल रिफ्रेश के साथ मैकेनिकल और हार्डवेयर अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं ।Ather 450X एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलेगी बड़ी बैटरी, बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने अपने नए एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है। बताया जा रहा है कि इसमें 3.66kWh का बड़ा लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया जा सकता है, जिसकी

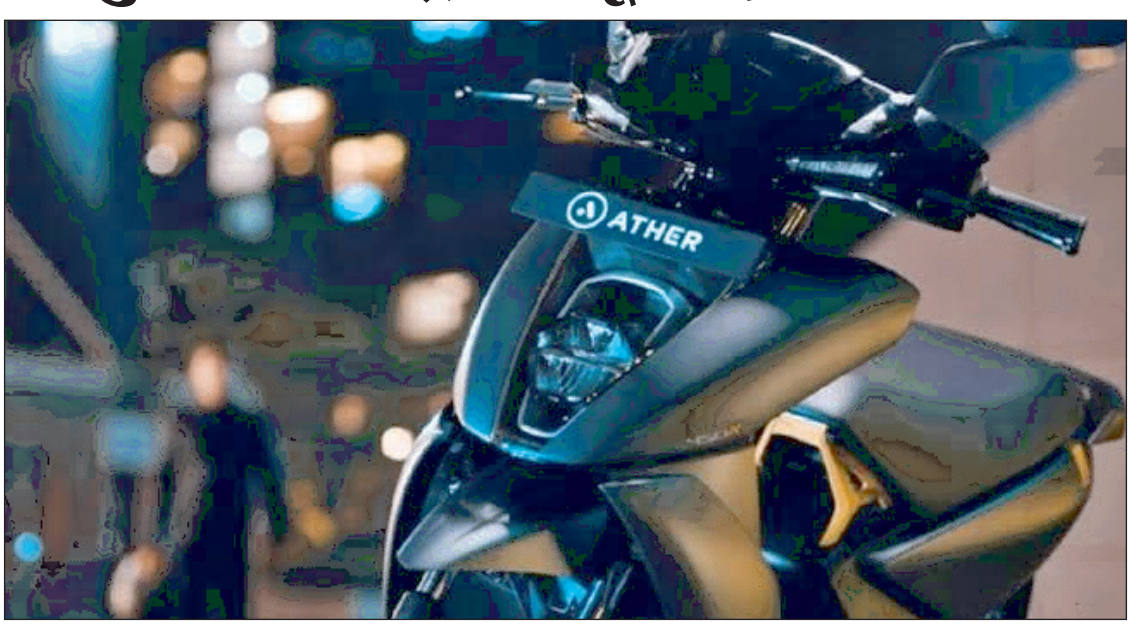

क्षमता 74 आह होगी। साथ ही, बैटरी उसी 3 चरण स्थायी चुंबक सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देगी जो वर्तमान 450X मॉडल में उपयोग की जाती है ।एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर को मिलेगी लंबी रेंज अधिक शक्तिशाली बैटरी से लैस, नई एथर 450X के बारे में कहा जाता है कि यह एक बार चार्ज करने पर लगभग 146 किमी की दूरी तय करती है।

वहीं देखा जाए तो यह मौजूदा मॉडल पर पेश किए गए 116 किमी के दायरे से ज्यादा है। वहीं, खबर है कि कंपनी ने नए 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर के निर्माण के लिए कथित तौर पर ARAI सर्टिफिकेशन से मंजूरी ले ली है। एक नया 3.66kWh बैटरी पैक आगामी एथर 450X को पावर देगा और इसे मौजूदा 2.6kWh यूनिट से अपग्रेड किया जाएगा। पीक पावर और टॉर्क का मॉड्यूलेशन पांच राइडिंग मोड्स, वार्प, स्पोर्ट, राइड, इको और स्मार्टइको में अलग-अलग होगा और रेंज को प्रभावित करेगा ।एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलेंगे राइडिंग मोड नए एथर 450X के प्रदर्शन को और बढ़ाने के लिए, कंपनी कई सवारी मोड पेश करने की भी योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए 450X में Warp Mode, Sport Mode, Ride Mode, Smart Eco Mode और Eco Mode दिए जाने की संभावना है।

इन मोड्स के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर Ola S1 Pro को चुनौती दे पाएगा ।एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया डिजाइन अधिकांश अन्य फेसलिफ्ट के विपरीत, एथर 450x लंबाई, व्हीलबेस और ऊंचाई में 25 मिमी, 9 मिमी और 11 मिमी बढ़ जाएगा। यह एर्गोनॉमिक्स और एथर 450X की सवारी और हैंडलिंग को प्रभावित कर सकता है। 2022 एथर 450X को नवीनतम फीचर सूची के साथ-साथ कॉस्मेटिक अपडेट मिलने की उम्मीद है ।एथर 450X 2020 मॉडल आपको याद दिला दें कि एथर 450X को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। भारत में एथर 450X की कीमत 1.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम बेंगलुरु) से शुरू होती है और ई-स्कूटर 116 किमी रेंज, 85 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड, एलईडी लाइटिंग और टचस्क्रीन से लैस है

संपादकीय

रक्षा निर्यात में वृद्धि

हमारा देश लंबे समय तक रक्षा साजो-सामान के सबसे बड़े आयातकों की सूची में रहा है, पर अब यह स्थिति जल्दी ही बदल जायेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही रेखांकित किया है कि बीते चार-पांच वर्षों की छोटी अवधि में रक्षा आयात में लगभग 21 प्रतिशत की कमी आयी है. घरेलू रक्षा उद्योग के तेज विस्तार से न केवल सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास हो रहा है, बल्कि रक्षा वस्तुओं का निर्यात भी लगातार बढ़ता जा रहा है. वित्त वर्ष 2021-22 में 13 हजार करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं अन्य देशों को बेची गयी थीं और इनमें से 70 फीसदी चीजों का उत्पादन निजी क्षेत्र के उद्योगों ने किया था. पहले की तुलना में सरकारी कंपनियों से खरीद का आंकड़ा बहुत बढ़ा है. सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आठ वर्षों में रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी होती रही है. पारंपरिक रूप से इसका बड़ा हिस्सा हथियारों और अन्य जरूरी चीजों के आयात पर खर्च होता रहा है, पर अब घरेलू खरीद बढ़ने से हम विदेशी मुद्रा की बचत करने के साथ अपने उद्योगों को ठोस सहायता भी पहुंचा रहे हैं. इससे औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार व कारोबार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. भू-राजनीतिक तनाव और कूटनीतिक खींचतान के कारण कई बार बाहर से हथियारों और रक्षा तकनीक की खरीद आसान नहीं होती. खरीद के बाद उन हथियारों की देख-रेख और उनके कल-पुर्जों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है. युद्ध जैसी स्थितियों में या किसी मुद्दे पर तनातनी होने से ऐसे लेन-देन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. घरेलू रक्षा उद्योग के विकास से ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है. अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्यरत है. इस अभियान का उद्देश्य है कि व्यापक घरेलू बाजार की मांग पूरी करने के साथ अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में भी भारत की ठोस उपस्थिति बने. रक्षा क्षेत्र में इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना के लिए 75 स्वदेशी तकनीकों और उत्पादों के विकास के कार्यक्रम की शुरुआत की है. वर्तमान में देश के भीतर 30 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण का कार्य चल रहा है. चार युद्धपोत नौसेना के बेड़े में जल्दी ही शामिल होंगे. इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों से अनिवार्य खरीद के लिए चिह्नित किया गया है. फ्रांस, रूस, इजरायल, फिलीपींस समेत अनेक देशों के साथ भारतीय कंपनियां कारोबारी समझौते कर रही हैं, जिनके तहत भारत में कई अहम चीजों और पुर्जों का निर्माण होगा तथा रक्षा तकनीक का विकास किया जायेगा. केंद्र सरकार ने 2020 में पांच वर्षों में रक्षा निर्यात को 35 हजार करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था. उम्मीद है कि 2025 तक भारतीय रक्षा उद्योग का टर्नओवर 1.75 लाख करोड़ रुपये हो जायेगा.

बरसात के मौसम में परेशान कर रहे हैं मच्छर और मक्खियां, अपनाएं ये टिप्स

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

बरसात का मौसम आ गया है। बारिश अपने साथ मच्छर और मक्खियां भी लेकर आती है। बारिश के कारन उमस भी बहुत हो जाती है इसलिए घर के खिड़की दरवाजे भी खोलने पड़ते है, और अगर आप घर के खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं तो मच्छर और मक्खियां बड़े मौज से आपकी मेहमान बनकर आ जाती हैं. खासकर जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहां दिन में दस बार दरवाजे खुलते और बंद होते हैं. ऐसे में मक्खियां दुनियाभर की गंदगी आपको बीमार करने के लिए अपने साथ लेकर आती हैं. अगर बीमारी का खतरा ना भी देखें तो इनकी भिन-भिन चैन से सोने-बैठने नहीं देती. पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जो आपके घर से इन मक्खियों को भागने पर मजबूर कर देंगे.

एपल साइडर विनेगर

एक गिलास में एपल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका लें और उसमें डिश सोप की कुछ बूंदें मिला लें. अब किचन में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक रैप को लेकर इस गिलास को ढक दें और गिलास पर प्लास्टिक रैप को रबड़ लगाकर टाइट कर लें. इसके बाद एक टूथपिक लेकर गिलास के मुंह पर लगे प्लास्टिक रैप पर जगह-जगह छेद कर दें. मक्खियों वाली जगह पर इसे रखें. जैसे ही मक्खियां इस गिलास पर आएंगी या अंदर जाने की कोशिश करेंगी तो डिश सोप के कारण बाहर नहीं निकल पाएंगी और अंदर ही डूबने लगेंगी.

नमक का पानी

एक गिलास पानी में 2 चम्मच भरकर नमक लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए. अब इस पानी को एक स्प्रे बोतल में भरिए और मक्खियों पर छिड़किए. यह मक्खियों को भगाने के लिए बेहद अच्छा है.

पुदीना और तुलसी

मक्खियों को भगाने के लिए पुदीना और तुलसी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. आप इन दोनों का पाउडर या पेस्ट बनाकर पानी में मिला सकते हैं. इस पानी को मक्खियों पर स्प्रे करें. यह कीटनाशक की तरह असर दिखाता है.

दूध और काली मिर्च

इस नुस्खे को तैयार करने के लिए एक गिलास दूध में एक चम्मच काली मिर्च और 3 चम्मच चीनी मिला लें. जहां भी मक्खियां सबसे ज्यादा घूमती हैं वहां इस दूध को रखें. मक्खियां इसकी तरफ आकर्षित होंगी लेकिन जल्द ही इससे चिपक कर डूब जाएंगी.

वीनस फ्लाईट्रैप

यह एक कार्निवोरस पौधा है जो कीड़े-मकौड़े खाता है. वीनस फ्लाईट्रैप पौधे को घर के बाहर या अंदर 1-2 कोनों पर लगा लें. इन पौधों का मुंह खुला रहता है और जैसे ही मक्खी इन पर आकर बैठती है तो ये उसे दबोच लेते हैं.

बाहरी राज्यों से आये किराएदारों और मजदूरों को दस्तावेजों के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना होगा शपथपत्र और अपने मूल थाने की सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में आकर कार्यरत एवं निवास कर रहे लोगों को अब सत्यापन प्रारूप में महज सामान्य विवरण देने के साथ ही उनके दस्तावेज सही हैं या नहीं इसके संबंध में एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपने साथ लायी गयी उनके मूल स्थान की सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। यह सभी दस्तावेज उन्हें मकान मालिक/प्रबन्धक/स्वामी के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने को प्रस्तुत करना होंगे।उल्लेखनीय है कि बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में आकर कार्यरत एवं निवासरत व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत एसओपी में संशोधन किया गया है।

जिसके अनुसार उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 83 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सत्यापन के सम्बन्ध में कूटरचित दस्तावेज या गलत शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।श्री अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने बताया कि बाहरी राज्यों को भेजे गये कतिपय सत्यापन प्रपत्रों पर सम्बन्धित बाहरी जनपद/थाने से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे व्यक्ति द्वारा पुलिस को प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की पुष्टि नहीं हो पाती है। इस संशोधन से सत्यापन प्रक्रिया सख्त बनेगी और संदिग्ध लोगों पर नजर रखकर कार्यवाही की जा सकेगी।

साक्षात्कार : धामी सरकार के मिशन 2025 को साकार करेगा एनएचएम - डॉ आर. राजेश कुमार , मिशन निदेशक

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून के पूर्व जिलाधिकारी और नवनियुक्त निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड डॉ आर राजेश कुमार ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। मूलतः तमिलनाडु से सम्बन्ध रखने वाले उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ आर राजेश कुमार को एक प्रभावशाली और कुशल प्रबंधक माना जाता है। यही वजह है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने अपने इस बेहतरीन अफसर को कमान सौंपी है। हिंदी दैनिक न्यूज़ वायरस से पहला साक्षात्कार देते हुए नवनियुक्त मिशन निदेशक एनएचएम ने अपनी प्राथमिकताएँ बताई हैं और कहा है कि वो सरकार की योजनाओं को प्रभावी बनाने में पारदर्शी और प्रभावी कार्य आने वाले दिनों में शानदार नतीजे देंगे। पढ़िए संवाददाता महविश के साथ मिशन निदेशक डॉ आर. राजेश कुमार का ये पहला इंटरव्यू -

महविश (रिपोर्टर) - निदेशक बनने के बाद डॉ आर राजेश कुमार सबसे पहला सवाल है कि आपके सामने क्या क्या चुनौतियां है ?

डॉ आर राजेश कुमार - स्वास्थ एक महत्वपूर्ण विभाग है , और जैसे कहते है वेल्थ इस वेल्थ और इसके साथ साथ कहना चाहूंगा कि उत्तराखण्ड में 13 जिले है और ज्यादातर पहाड़ी ज़िले है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से कोने कोने तक जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं और सुविधाएं हैं वो हर व्यक्ति तक आसानी से पहुँचाना ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है

महविश (रिपोर्टर) - अगले कुछ दिनों के लिए आपकी पहली 5 प्रमुख प्राथमिकता क्या रहेगी ... ?

डॉक्टर आर. राजेश कुमार - इस सवाल का जवाब देते हुए मिशन निदेशक डॉ राजेश कुमार कहते हैं कि अभी फिलहाल उन्होंने चार्ज लिया है और अभी वह विभागीय अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जो दिमाग में परिकल्पना बनाई है और मुख्यमंत्री के विजन और विभागीय मंत्री की योजनाओं को साकार करने के लिए उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है वह समझते हैं। अभी फिलहाल सबसे पहले आम आदमी और हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना सबसे पहली प्राथमिकता है , डॉक्टर नर्स एएनएम के साथ मिलकर योजनाओं को पहाड़ों पर ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाकर मरीजों और अस्पतालों में आने वाले लोगों को राहत देना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके साथ ही साथ क्योंकि यह पहाड़ी राज्य है और कहीं ऐसी जगह भी हो सकती है , जहां स्वास्थ्य सेवाएं न पहुंच पाई हो ऐसे में इन जगहों पर फर्जी डॉक्टर , फर्जी झोलाछाप सेंटर भी बन जाते हैं जिसकी वजह से लोगों की जान माल का नुकसान होता है और इसलिए इन पर सख्त कार्यवाही करना भी प्लान में शामिल है।

महविश (रिपोर्टर) - अक्सर यह देखा जाता है की आम जनता से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स अच्छे से व्यवहार नहीं करते है तो इसका क्या उपाय है आपके पास ?डॉक्टर आर. राजेश कुमार - इस सवाल के जवाब में डॉ राजेश कुमार कहते हैं कि उन्होंने फिलहाल अभी चार्ज लिया है और हालात कैसे हैं ? और स्थिति क्या है ? इसके बारे में वह कुछ दिनों बाद ही बता पाएंगे , लेकिन पहले वह लगातार मीटिंग लेंगे और अपने विभाग के सभी अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे क्योंकि जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार का स्वस्थ और तंदुरुस्त उत्तराखंड बनाने का जो लक्ष्य है और जिसके लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है उसमें आम आदमी तक एनएचएम की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा सके , आशा और एएनम इसमें काफी मददगार होती हैं इसलिए अभी फिलहाल कुछ दिन तक विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लेंगे उसके बाद अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे

महविश (रिपोर्टर) - देहरादून में नकली दवाइयों की कालाबाजारी का गैंग काम कर रहा है तो आप क्या उसको रोक पाएंगे ?

डॉक्टर आर. राजेश कुमार - इस सवाल के जवाब में मिशन निदेशक एनएचएम डॉ आर. राजेश कुमार कहते हैं कि जब वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तब भी उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम बनाकर लगातार फर्जी दवाइयों के कालाबाजारी पर सख्त कार्यवाही की थी और बड़े पैमाने पर रोक लगाने में कामयाब हुए थे। ऐसे में उन्होंने जो अभियान दवाइयों की ब्लैक मार्केट को तबाह और खत्म करने के छेड़ा था जो अब इस कुर्सी पर आकर भी वह आगे जारी रखेंगे ताकि जनता की जान के साथ खिलवाड़ हरगिज़ न हो सके।

महविश (रिपोर्टर) - अंत मे एक ज़रूरी सवाल है कि सरकारी अस्पतालो मे ऐम्बुलेंस गैंग काम करता है ज़ाहिर बात है इसमे डाक्टर्स भी साथ देते है सरकारी अस्पतालो से मरीज़ो को प्राइवेट अस्पतालो मे छोड़ा जाता है , तो क्या आप इस गैंग को तोड़ पायंगे ?

डॉक्टर आर. राजेश कुमार - अस्पतालों में एंबुलेंस बैंक के मकड़जाल को तोड़ने के लिए डॉक्टर आर. राजेश कुमार कहते हैं कि न्यूज़ वायरस ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है उसके लिए वह धन्यवाद करना चाहते हैं , साथ ही साथ जिस तरह से इस समस्या पर इनपुट और फीडबैक मिलेगा वो सख्त कार्यवाही उसी तरह जारी रखेंगे जिस तरह जिलाधिकारी रहते हुए उन्होंने जिला प्रशासन में सख्त और पारदर्शी कार्यवाही और कार्यप्रणाली को शुरू किया था। मिशन निदेशक एनएचएम के रूप में वो लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उनसे जो भी उम्मीदें राज्य सरकार ने की है , विभागीय मंत्री और जनता ने की है उस पर वह पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यही उम्मीद उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी जताई है।

महविश (रिपोर्टर) - अंत में आप उत्तराखंड की जनता को क्या सन्देश देना चाहेंगे ?

डॉ आर. राजेश कुमार - जवाब देते हुए मिशन निदेशक कहते हैं कि अभी कोविड का खतरा बना हुआ है और हमे अभी फिलहाल सभी सावधानिया बरतनी है। लिहाज़ा मैं जन समुदाय से विनम्र अनुरोध करूंगा की हम सरकार के जो बनाय हुए गाइडलाइन्स है उसका सख्ती से पालन करे और अपने आस पास के लोगो को भी जागरूक करे। एक और मेसेज मैं देना चाहूंगा डेंगू के सम्बन्ध मे , हर 3 साल मे डेंगू का आउटब्रेक सबसे ज़्यादा चरम पर रहता है। तो यह वह साल है जिसमे सबसे ज़्यादा संभवता डेंगू आउटब्रेक इंटर्म ओफ नम्बर्स सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपने आसपास साफ सफाई रखिए , पानी को अपने आस पास जमा न होने दें। आप एक ज़िम्मेदार और जागरूक नागरिक बनकर न सिर्फ अपनी सेहत को बचा सकते हैं बल्कि अपने शहर और राज्य की भी सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर मारा छापा,हरिद्वार में कावडियों के बीच अचानक पहुंचने से सब रह गए दंग

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हरिद्वार,20 जुलाई। प्रभारी सचिव स्वास्थ डॉ आर राजेश कुमार ने किया कांवड़ मेले का औचक निरीक्षण राहत कैंप की देखी व्यवस्थाएं दवाइयां एंबुलेंस आदि समय पर उपलब्ध कराने के दिए निर्देश।प्रभारी सचिव बनने के बाद पहली बार डॉ आर राजेश कुमार कांवड़ मेले में चिकित्सीय सुविधा व्यवस्था जाँचने हेतु हरिद्वार पहुंचे ।कांवड़ मेले में लोगों को हो रही समस्या दवाइयों की व्यवस्था जिला अस्पताल में डॉक्टरों की व्यवस्था का उन्होंने औचक निरीक्षण कर अनेक समस्याओं का समाधान भी कियामौके पर राहत कैंप पहुंचे और मौके पर मौजूद कावड़ियों से प्रभारी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ आर राजेश कुमार ने बात की और कांवड़ मेले में हो रही सुविधा और असुविधा के संबंध में चर्चा की और फिर बताया कि कावडियो को इस यात्रा सीजन में मुख्य रूप से फंगल इंफेक्शन जो पैरों में हो जाता है इसके अलावा सांप के काटने की जो घटना है वह ज्यादातर हो रही है उसको देखते हुए मेडिकल कैंप में सांप के काटने पर उपचार हेतु दवाई की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा फंगल इंफेक्शन से रिलेटेड दवाइयों की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लगाए हैं 25 राहत कैंप पूरे हरिद्वार शहर में 25 जगहों पर मेडिकल कैंप लगाया गया है जिसमें औसतन 1000 लोग प्रतिदिन कैंप का लाभ उठा रहे हैं ।डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि हरिद्वार में 6 स्थानों पर मुख्य कैंप लगाया गया है जिसमें अधिकाधिक श्रद्धालु लाभ ले रहे हैं जिसमें प्रतिदिन औसतन 2000 लोग उपचार ले रहे हैं । हर की पैड़ी पर मुख्य कैंप लगाया गया है जहां पर सभी तरह की व्यवस्थाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद हैजिला अस्पताल का भी किया निरीक्षणऔचक निरीक्षण के बाद डॉ आर राजेश कुमार ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि वहां सर्जन की व्यवस्था नहीं है प्रभारी सचिव ने जल्द से जल्द वहां सर्जन नियुक्त करने की बात कही है हर की पैड़ी पर मुख्य कैंप लगाया गया है । प्रभारी सचिव ने निर्देश दिया है कि हरिद्वार जिले के अस्पतालों की जहां भी डॉक्टरों की समस्या है उसकी सूची जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए ताकि उचित कार्रवाई किया जा सकेगंभीर मरीजों के लिए एंबुलेंस की 24 घंटे की सेवाजहां पर अधिकाधिक श्रद्धालुओं को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है स्थानीय स्तर पर एंबुलेंस की व्यवस्था भी राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने की है ।गंभीर परिस्थिति में कांवरियों को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाने के लिए 24 घंटे एंबुलेंस तैयार है प्रभारी सचिव ने यही बताया कि दवाइयों की उचित व्यवस्था एंबुलेंस के अंदर हूं मौजूद है इसके अलावा ऑक्सीजन एवं अन्य उपकरण के साथ एंबुलेंस तैयार कर दी गई है कांवरियों को सभी प्रकार की दवाइयों की सुविधा मिल रही है जिसकी निगरानी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है ।। कांवरियों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताप्रभारी प्रभारी सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि पूरे देश से आने वाले श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में स्वागत है हम उनके स्वास्थ्य के प्रति है संकल्पित हैं सभी कांवरियों को उचित स्वास्थ्य और सेवा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार दे रही है ।हम इस को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं हर स्तर पर उत्तराखंड सरकार दवाइयों की व्यवस्था एंबुलेंस की व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं ।।

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा